वर्ष : 03– अंक : 25 – अप्रैल 2025

International Year of Cooperatives 2025

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार उदय

उन्नत देसी बीजों से बदलेगी खेती

किसानों की समृद्धि का आधार बनेगा बीज अनुसंधान केंद्र 12

सशक्त होगा सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण 14

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

अनुक्रमणिका

सहकार उदय

अप्रैल 2025, अंक 25, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
संतोष कुमार शुक्ला

संपादक
रोहित कुमार

सह संपादक
अँक अँजलीदीप

सदस्य
माधवी एम. विप्रदास
विवेक सक्सेना
हितेंद्र प्रताप सिंह
राशिद आलम

सहकार उदय से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।

sahkaruday@iffco.in

महाप्रबंधक (सहकारिता विकास)
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

इफको से जुड़ने के अन्य पते:

Iffco.coop

IFFCO_PR

Iffco_coop

प्रकाशक-इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
मुद्रक-रॉयल प्रेस, ओखला, नई दिल्ली

उन्नत देसी बीजों से बदलेगी खेती

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार बहुआयामी विकासमूलक योजनाओं को गति दे रही है। इसके लिए ग्रामीण समृद्धि की दिशा में भी ठोस एवं बुनियादी पहल किए जा रहे हैं।

आवरण कथा — पेज 06 देखें

पेज 18 देखें

विकास में महत्वपूर्ण होगी नीली अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस क्षेत्र में तमिलनाडु की ताकत को वैश्विक स्तर पर पहचाना जाएगा।

पेज 20 देखें

ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले करीब 11 सालों में भारत 'ग्लोबल लीडर' बनने की दिशा में आगे बढ़ा है और देश के हर क्षेत्र में अनेक प्रकार की व्यवस्था एवं विकास का सूत्रपात हुआ है।

पेज 22 देखें

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता

पेज 24 देखें

सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन को देख नक्सलियों की कांप जाती है रूह

पेज 26 देखें

वक्फ के धार्मिक दान के कामों में नहीं होंगे गैर-मुस्लिम

पेज 28 देखें

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से सहकारिता का भविष्य होगा उज्ज्वल

पेज 25 देखें

जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

पेज 29 देखें

सहकारी संस्था इफको की प्राथमिकताओं में साहित्य व संस्कृति भी शामिल

बीज से बाजार तक होगी भारत की बढ़त

देश में सहकारिता ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का व्यापक आधार बन रही है। देश की कृषि व्यवस्था में सुधार और खेती को लाभकारी बनाने के लिए सहकारिता क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास हो रहे हैं। इस दिशा में एक दूरगामी पहल करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) का गठन किया है जो किसानों को प्रमाणित एवं उन्नत किस्म के घरेलू बीज सुलभ कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से देश में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही बीजों के लिए आयात पर निर्भरता को समाप्त करेगा और भारत को बीजों के निर्यात के लिए समर्थ बनाने में योगदान करेगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में शीर्ष सहकारी संस्था इफको ने गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में बीज अनुसंधान केंद्र की नींव रखी है। यह बीज केंद्र किसानों की समृद्धि बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा और बीज उत्पादन में बड़ा योगदान करेगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस अनुसंधान केंद्र की बुनियाद रखते हुए इफको एवं सभी सहकारी संगठनों से सहकारी क्षेत्र के जरिये बेहतर और परंपरागत बीजों के उत्पादन में योगदान करने का आह्वान किया और कहा कि यह कदम देश में फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। फसलों की पैदावार में सुधार लाने और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन से खेती में बहुमूल्य बदलाव आएगा।

सहकारी समितियों के माध्यम से बीबीएसएसएल भारत में गुणवत्तापूर्ण देसी बीजों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे आयातित बीजों पर हमारी निर्भरता कम होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। कृषि उत्पादन बढ़ने से निश्चय ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, और देश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। सहकारी समितियों के माध्यम से यह बदलाव देश की कृषि व्यवस्था में एक वरदान साबित होगा। बीबीएसएसएल प्रमाणित बीजों के उत्पादन में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके बीज प्रतिस्थापन दर और विविध प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने में मदद करेगी। यह प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेवलिंग और पैकेजिंग पर फोकस करेगी।

'सहकार उदय' पत्रिका के इस अंक में 'सहकारी बैंकिंग' विषय पर सारगर्भित आलेखों के साथ अन्य उपयोगी जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं। हमें विश्वास है कि यह अंक आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होगा। ■

सादर धन्यवाद

जय सहकार

International Year of Cooperatives 2025

Cooperatives Build a Better World

बीते एक दशक में हमने अपने गरीब भाई-बहनों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर मिशन मोड पर काम किया है, जिससे उनका जीवन बहुत आसान हुआ है। हमने विकास के रास्ते की कई रुकावटों को दूर किया है, जिससे देश का पूरा सामर्थ्य देशवासियों के काम आ रहा है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मोदी सरकार में सहकारिता, ग्रामीण भारत के आर्थिक सशक्तिकरण का केंद्र बन रही है। श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से सहकारी डेयरी क्षेत्र को नया जीवन मिल रहा है। गांव-गांव में डेयरी कोऑपरेटिव के पहुंच का सीधा फायदा डेयरी क्षेत्र के किसानों को होगा।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

भारत को मिला पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय। केंद्र सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करके जमीनी स्तर पर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

श्री मुरलीधर मोहोल,
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

गुजरात की शांति का मुख्य राज सहकारिता के माध्यम से मिल रही रोजगारी है। सरदार पटेल, त्रिभुवनदास पटेल, उदयभाण सिंह एवं वैकुंठ महेता के समय से कार्यान्वित सहकारी गतिविधियां को और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

इफको नैनों उर्वरकों के बेहतरीन उत्पादन, विपणन व इफको के वित्तीय लाभ के लिये सभी ने बेहतरीन कार्य किया। पिछले वित्त वर्ष में इफको के बेहतर परिणामों में संपूर्ण इफको परिवार, किसानों और सहकारी बंधुओं का सफल योगदान रहा।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी,
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इफको

भारत में इफको के "बीज अनुसंधान कैंद्र" किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ कृषि क्षेत्र में नवाचार और समावेशी विकास को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करेंगे।

सहकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

देश के सभी गांवों में सहकारी समितियों का हो रहा विस्तार

सहकार उदय टीम

➲ ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के एक सुदृढ़ मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में सहकारी क्षेत्र में हो रहे अनेक बहुआयामी पहल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश में सहकारी क्षेत्र को व्यापक आयाम प्रदान कर रही है। सहकारिता को ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के एक मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में अनेक बहुआयामी पहल हो रहे हैं। इसके साथ ही देशभर में अब तक सहकारी समितियों की पहुंच से वंचित रहे गांवों में दो लाख नई सहकारी समितियां खोली जा रही हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में भारतीय संसद में इस आशय की जानकारी साझा किया। एक प्रश्न के लिखित जवाब में श्री शाह ने कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से देश के सभी पंचायतों व गांवों को कवर करने के लिए दो लाख नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार की कई मौजूदा योजनाओं, जैसे- डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि को इसके जरिए विस्तार मिलेगा। इसें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार की योजनाओं को फैलाने से नवगठित डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों में विविधीकरण लाने के लिए दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं जैसे आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने और आधुनिकीकरण करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

श्री शाह ने संसद के माध्यम से देशवासियों को बताया कि पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पैक्स के लिए मॉडल बॉयलॉज का निर्माण किया है, जो पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, प्रसंस्करण, कृषि उपज की मार्केटिंग, कस्टम हायरिंग केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) और सामुदायिक सिंचाई आदि सहित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाते हैं। बहुउद्देशीय पैक्स के तौर पर नए पैक्स का पंजीकरण उन्हें और साथ ही उनके किसान सदस्यों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने, बाजारों और क्रेडिट तक अपनी पहुंच का विस्तार करने और अपने लिए राजस्व के अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2025 तक देशभर में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 12,957 नई एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं और इन समितियों के साथ 17,10,224 किसान सदस्य जुड़े हुए हैं। इन नवगठित सहकारी समितियों के गठन से उनसे जुड़े किसान सदस्यों को अपने कृषि उत्पादों की मार्केटिंग, अपने बाजारों के आकार का विस्तार करने, अपनी आय बढ़ाने, क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने और गांव स्तर पर ही अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संपर्क प्राप्त करने में मदद मिलती है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान मिलता है।■

7/10/25, 4:17 PM Sahkar Uday 25 Issue - Hindi

उन्नत देसी बीजों से बदलेगी खेती

सहकार उदय टीम

➲ 19,674 सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य

➲ सात वर्षों में 18 हजार करोड़ रुपए के बीजों का कारोबार

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार बहुआयामी विकासमूलक योजनाओं को गति दे रही है। इसके लिए ग्रामीण समृद्धि की दिशा में भी ठोस एवं बुनियादी पहल किए जा रहे हैं। गांवों में रहने वाली देश की बहुत बड़ी आबादी के जीविका के मुख्य साधन कृषि कार्य को लाभकारी बनाने और अन्नदाता किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सहकारी क्षेत्र में जो बहुत से प्रयास किए जा रहें हैं, उनमें किसानों को उत्तम गुणवत्ता युक्त देशी कृषि बीजों को सुलभ कराने के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना एक अभिनव पहल है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र में बीबीएसएसएल की अहम भूमिका होगी। बीबीएसएसएल की स्थापना फसल उपज में सुधार लाने और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित करते हुए सहकारी नेटवर्क के माध्यम से भारत ब्रांड के तहत गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, खरीद और वितरण करने के लिए की गई है। बीबीएसएसएल सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। श्री शाह ने कहा कि यह सहकारी संस्था भारत के बीज उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाली है। बीबीएसएसएल भारत के स्वदेशी व पारंपरिक बीजों की रक्षा करेगी और इस दौरान उनकी जेनेटिक व शुद्धता भी सुनिश्चित करेगी। यह गवगठित सहकारी संस्था आने वाले वर्षों में बीजों के संरक्षण, संवर्द्धन और शोध कार्य में महत्त्वपूर्ण योगदान देगी। बीबीएसएसएल भारत से प्रमाणित बीजों का निर्यात बढ़ाएगी। इस सहकारी का पूरा लाभ किसानों में बांटा जाएगा।

देश में फसलों की पैदावार में सुधार लाने और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित करने की दिशा में बीबीएसएसएल युगपरिवर्तनकारी भूमिका में है। देसी बीजों के संरक्षण-संवर्धन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की इस

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/bzqs/ 6/32

> भारत उन गिने-चुने देशों में है जहां प्राचीन समय से खेती की जा रही है। लिहाजा हमारे पारंपरिक बीज प्रकृति के अनुकूल हैं और स्वास्थ्यवर्धक हैं। अभी ऐसे बीजों की विश्व में मांग बहुत ज्यादा है। हमें पारंपरिक बीजों का संरक्षण करने की जरूरत है और इससे स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार होता है। इसे बीबीएसएसएल के जरिए किया जाएगा।
>
> - श्री अमित शाह
>
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

शीर्ष सहकारी बहु-राज्यीय बीज समिति का मुख्य दायित्व सहकारी समितियों के माध्यम से देश में गुणवत्ता संपन्न बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करना है। बीज समिति की सफलता से स्वाभाविक रूप से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे आयातित बीजों पर हमारी निर्भरता कम होगी और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा। इससे निश्चय ही भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।

18 हजार करोड़ रुपए के बीजों का कारोबार का लक्ष्य

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार बीबीएसएसएल ने पहले कारोबारी वर्ष यानी 2025-26 में 270 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। संस्था ने अगले सात वर्षों में 19 लाख टन बीजों की बिक्री के साथ 18 हजार करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। यह शीर्ष सहकारी संस्था वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि अब तक देशभर की 19,674 सहकारी समितियां बीबीएसएसएल के सदस्य के रूप में जुड़ चुकी हैं। बीएसएसएल ने झारखंड सरकार से बीज लाइसेंस हासिल कर लिया है। इसकी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था झारखंड के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में भी किसानों को समय पर बीज मुहैया कराएगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर बहुराज्य सहकारी समिति बीबीएसएसएल का गठन वर्ष 2023 में किया था। समिति के नियंत्रण और निर्देशन के लिए पांचों प्रवर्तक संस्थाओं से एक-एक प्रतिनिधि को चुनकर अंतरिम बोर्ड का गठन किया और जुलाई, 2023 में वैधानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नियमित बोर्ड का गठन किया, जिससे बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के बाद इफको के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार को सर्वसम्मति से बीबीएसएसएल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड

7/10/25, 4:17 PM Sahkar Uday 25 Issue - Hindi

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

बीज उत्पादन में बड़ी सहकारी समितियों की अहम भूमिका

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत की है। देश में सहकारी क्षेत्र के शीर्ष संस्थानों-इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को बीबीएसएसएल का प्रमोटर बनाया गया है। बीबीएसएसएल की आरंभिक पूंजी 250 करोड़ रुपए निर्धारित की गई, जिसमें इन पांचों प्रवर्तकों का 50-50 करोड़ रुपए का योगदान है। बीबीएसएसएल की अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपए तय की गई है।

यह समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर पैक्स के द्वारा दो पीढ़ियों के सभी बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी के *'सहकार से समृद्धि'* के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन से सहकारिता से जुड़े किसानों को जहां अपने उत्पादों की बेहतर कीमत मिलेगी, वहीं उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों के उपयोग से फसलों का अधिक उत्पादन होगा।

बीबीएसएसएल की सदस्यता के लिए खरीदने होंगे शेयर

भारतीय बीज सहकारी सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए इसका शेयर लेना होगा। राज्य स्तरीय सहकारी समितियों को न्यूनतम 1000 शेयर खरीदने होंगे, जिसका मूल्य प्रति शेयर 1000 है। इस तरह कुल एक लाख रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरह अगर कोई राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बीबीएसएसएल का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे कम से कम 500 शेयर खरीदने होंगे, जिसकी कीमत (प्रति शेयर 1000 रुपये) 50,000 रुपए होगी। इसी तर्ज पर राज्य स्तर की प्राथमिक सहकारी समितियां भी सदस्य बन सकती हैं। इसके लिए उन्हें 10 शेयर खरीदने होंगे जिसका मूल्य 10,000 रुपए होगा। जबकि निचले स्तर की प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) को सदस्यता पाने के लिए एक हजार रुपए मूल्य के बराबर का एक शेयर खरीदना होगा।

गैर सहकारी संगठनों को भी इसकी सदस्यता मिल सकती है। इसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त संगठनों को भी कम से कम दो शेयर (प्रति शेयर एक हजार रुपए मूल्य) खरीदने की छूट होगी। शेयर खरीदने के निए निर्धारित 500 रुपए मूल्य के फार्म को भरकर शेयर की कीमत जमा करनी होगी। बीबीएसएसएल के सभी सदस्यों को वार्षिक 20 प्रतिशत का अधिकतम लाभांश दिया जाएगा।

ने वित्तीय वर्ष के शुरुआत से ही सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार ने किसान ऐप के माध्यम से सभी सहकारी समितियों से जल्द ही अपना पंजीकरण करा लेने का आह्वान किया। बीबीएसएसएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीबीएसएसएल की सदस्यता के लिए अब तक देश भर की सहकारी समितियों से कुल 20,961 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 17425 को शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके थे। बीबीएसएसएल की सदस्यता के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्यों व जिला समितियों और पैक्स की सदस्यता का अभियान चलया जा रहा है। इनके लिए न्यूनतम शेयर खरीदने की सीमा तय की गई है। वहीं, कोई भी व्यक्ति या संस्था एक लाख रुपए का शेयर खरीदकर सदस्यता हासिल कर सकता है, लेकिन उनको मताधिकार नहीं होगा, लेकिन वह बीबीएसएसएल के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर कारोबार कर सकते हैं।

सदस्यों को मिलेगा 20 प्रतिशत तक लाभांश

बीबीएसएसएल के मुनाफे में से सदस्यों को उनकी शेयर पूंजी के आधार पर 20 फीसदी तक का लाभांश दिया जाएगा। इस तरह सहकारी समिति के सदस्य किसानों को बीज के उत्पादन से बेहतर दाम के अलावा लाभांश का भी फायदा होगा। बीबीएसएसएल 11 राज्यों में बीज लाइसेंस हासिल कर चुकी है और पांच राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। बीबीएसएसएल ने ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड सभी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। वर्ष 2024-25 में मूंगफली, गेहूं, जई और बरसीम के बीज की बिक्री से शुरुआत की गई है।

इस शीर्ष बीज सहकारी समिति को विभिन्न राज्यों से बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं विपणन के लिए स्वीकृति पत्र मिल चुके हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत सहकारी संस्थाओं को बीज उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सहकारी समितियां अपने बीज बेचने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क करके निविदाओं में शामिल हो रही हैं। भारत सरकार ने भारतीय बीज सहकारी

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/bzqs/ 8/32

कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव लाएगा बीबीएसएसएल

समिति को दालों एवं तेल वाली फसलों में बीजों के वितरण के लिए नोडल संस्थाओं में शामिल किया है। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर वर्ष 2023-24 की रबी फसलों बीज के उत्पादन के लिए देश के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में 78 बीज उत्पादकों के प्रक्षेत्रों में लगभग 1100 एकड़ क्षेत्र में गेंहू, चना, सरसों एवं मटर फसलों के उत्पादकों से आधारीय बीजों का उत्पादन कराया गया और इन बीजों का वर्ष 2024-25 की रबी फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन में प्रयोग किया गया। भारतीय बीज सहकारी समिति ने बड़ी तैयारी करते हुए सात वर्षों में 18 हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। इसके तहत पहले कारोबारी वर्ष यानी 2025-26 में 270 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है।

इसप्रकार, निकट समय में भारत सरकार के कृषि एवं अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर सहकारिता मंत्रालय बीबीएसएसएल के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के सहयोग से उन्नत एवं पारंपरिक बीजों के उत्पादन एवं वितरण में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा और उन्नत एवं प्रमाणिक बीजों के माध्यम से कृषि कार्य को एक लाभकारी कारोबार के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। इस महत्वपूर्ण सहकारी प्रगति में प्राथमिक सहकारी समितियों की अहम भूमिका होगी। वर्ष 2025-26 के रबी फसल सत्र से बीबीएसएसएल के माध्यम से उत्पादित उन्नत बीजों का व्यवसाय शुरू होने जा रही है और इसके लिए कई राज्यों की संस्थाओं के साथ व्यवसायिक समझौते भी किए गए हैं।

उन्नत बीजों की मांग को पूरा करेगा बीबीएसएसएल

बीबीएसएसएल ने छोटे और सीमांत किसानों के बीच 'भारत बीज' को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है। इसमें सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए जागरूकता अभियान, किसानों की बैठकें, क्षेत्रीय कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रदर्शनियां शामिल हैं। राज्यों के कृषि विभाग भी अपने स्तर पर प्रशिक्षण सत्र, वर्कशॉप और फील्ड प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

वैश्विक बीज उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम होने पर दुख जताते हुए श्री शाह ने कहा कि किसानों को वैज्ञानिक रूप से तैयार प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इससे न केवल किसान प्रभावित हो रहे हैं बल्कि देश का खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल, भारतीय कृषि क्षेत्र का यह एक दुखद सत्य है कि भारत में करीब-करीब पचास प्रतिशत किसान ही गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करते हैं और बाकी किसान खेतों में संरक्षित बीजों पर ही निर्भर हैं। बीबीएसएसएल की स्थापना का अहम लक्ष्य देश में प्रसंस्कृत और गुणवत्ता वाले बीज से वंचित 53 प्रतिशत क्षेत्र को उस 47 प्रतिशत क्षेत्र के साथ बराबरी पर लाना है जहां बेहतर

International Year of Cooperatives 2025

किस्मों के गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हैं। उन्नत देसी बीजों की अनुपलब्धता की इस बड़ी खाई को पाटने के लिए ही सहकारिता मंत्रालय ने बीबीएसएसएल की स्थापना की है, जो सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से दो पीढ़ियों के बीजों, यानी फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग जैसी सभी गतिविधियों को करने में शीर्ष भूमिका निभाएगी। ब्रीडर बीज सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान संगठनों और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों, जैसे कि अर्द्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी), अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) और अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (सीआईएमएमवाईटी) आदि से प्राप्त किए जाएंगे। अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए बीबीएसएसएल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाएगा और निजी सहित सभी उपलब्ध मार्केटिंग चैनलों के माध्यम से 'भारत बीज' ब्रांड के तहत किसानों को प्रामाणिक गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यह अपेक्स सोसाइटी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम से दो पीढ़ियों के बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेवलिंग और पैकेजिंग पर फोकस करेगी।

चालू फसल वर्ष में डेढ़ लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का अनुमान

बीबीएसएसएल ने 2024-25 में अब तक अनाज, तिलहन और चारा फसलों के 52,906 क्विंटल बीज वितरित किए हैं। 138 खुदरा विक्रेताओं व वितरकों के माध्यम से बेचे गए इन बीजों का कुल मूल्य करीब 46.19 करोड़ रुपए है। इस सहकारी संस्था को 11 राज्यों में बीजों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त हो चुका है और अन्य पांच राज्यों में यह प्रक्रियाधीन है। बीबीएसएसएल ने अब तक 577 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 15,395 क्विंटल बीज 9 का उत्पादन किया है, जिसमें 23 किस्म की 9 फसलें शामिल हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बीबीएसएसएल ने रबी सीजन 2023-24 में 13,697 क्विंटल फाउंडेशन बीज का उत्पादन किया और रबी सीजन 2024-25 में भी गेहूं, चना, सरसों और मटर के करीब साढ़े छह लाख क्विंटल सर्टिफाइड बीजों का उत्पादन हुआ। इस दौरान लाभार्थी किसानों की संख्या 16,850 से बढ़कर 20.96 लाख हो गई है। इस दौरान बीजों की बिक्री से 1790 सहकारी समितियां भी लाभ प्राप्त कीं। वहीं, वर्ष 2025-26 में 21 लाख किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। खरीफ 2025 सीजन में सात फसलों- धान, चना, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, मक्का और बीन्स की 22 वैरायटी के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका 1.6 लाख क्विंटल सर्टिफाइड बीज उत्पादन का अनुमान है जिससे 56.47 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

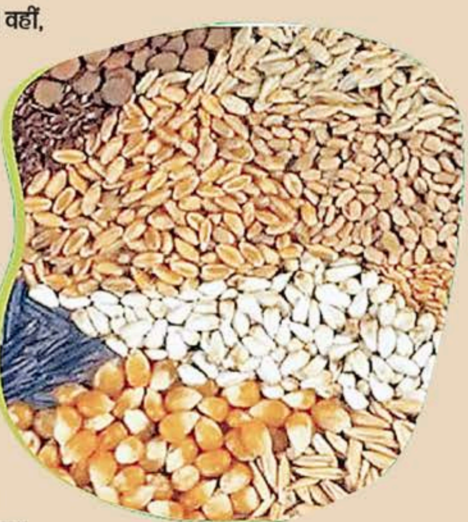

बीबीएसएसएल ने कृषि अनुसंधान संस्थानों से हाथ मिलाया

देश में रोग प्रतिरोधी बीज किस्मों को विकसित करने और खेती में ज्यादा पैदावार पाने की इन संकल्पनाओं को साकार करने के लिए बीबीएसएसएल ने कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत बीबीएसएसएल ने विभिन्न फसलों और किस्मों के आनुवंशिक रूप से उच्च क्षमता और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रजनक बीज प्राप्त करने और फाउंडेशन व प्रजनक बीजों को बढ़ावा देने के लिए एक सार्थक पहल करते हुए प्रमुख अनुसंधान संगठनों को साथ लिया है। इस योजनाबद्ध पहल के तहत जिन प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली ; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पीएयू), पंजाब ; भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर),

7/10/25, 4:17 PM Sahkar Uday 25 Issue - Hindi

बीते रबी सीजन में 11,594 क्विंटल फाउंडेशन बीज का उत्पादन

'भारत बीज' के वितरण के लिए खुदरा दुकानें स्थापित

बीते खरीफ सीजन में 10 राज्यों में सात फसलों की 23 किस्मों की बुवाई

5,596 हेक्टेयर में 1,64,804 क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन

विभिन्न फसलों के 38,126 क्विंटल बीज वितरित

बीबीएसएसएल को एक दर्जन राज्यों में मिला लाइसेंस

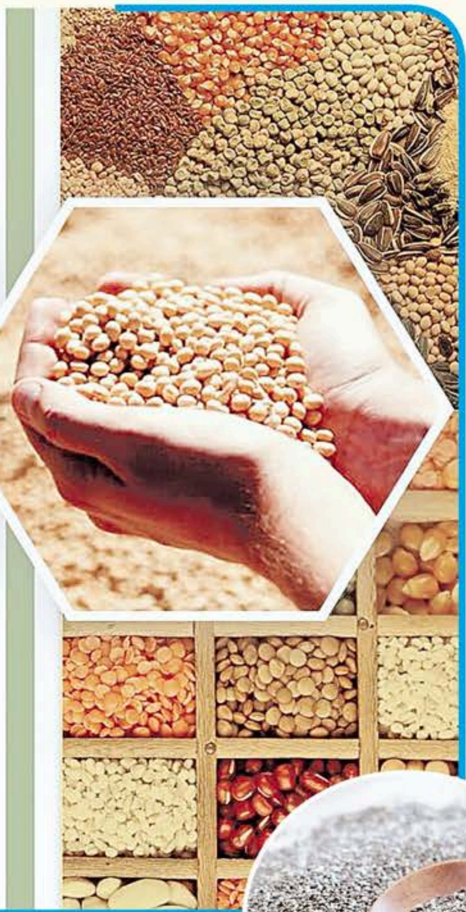

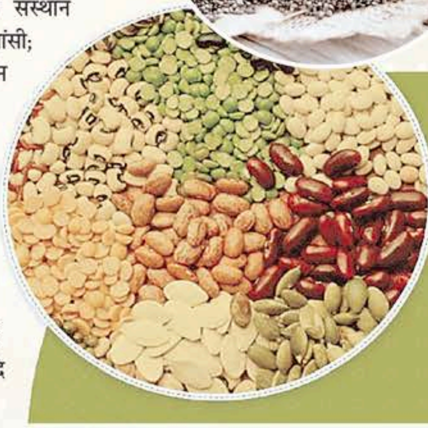

लुधियाना, पंजाब ; भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद, तेलंगाना ; जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड और क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं व्यवसाय योजना और विकास इकाई आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली शामिल हैं।

बीबीएसएसएल इन सबके इतर भी कई सार्थक पहल कर रहा है। यह शीर्ष बीज सहकारी समिति कुछ लक्षित फसलों में भारतीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप उच्च उपज वाली, रोग प्रतिरोधी और विशिष्ट गुणों वाली संकर किस्मों के विकास की दिशा में पहल कर रहा है।

इसके लिए जिन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग के लिए पहल की गई है, उनमें अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद; अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई), वाराणसी; भारतीय ग्रास और चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई), झांसी; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर), वाराणसी ; भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर ; राष्ट्रीय मक्का और ज्वार अनुसंधान केंद्र; तथा वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर, थाईलैंड एवं कासेट्सार्ट विश्वविद्यालय, थाईलैंड आदि शामिल हैं। ■

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/bzqs/ 11/32

इफको की कलोल इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले श्री अमित शाह

किसानों की समृद्धि का आधार बनेगा बीज अनुसंधान केंद्र

सहकार उदय टीम

- इफको ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के माध्यम से पूरे विश्व में भारत के कोऑपरेटिव क्षेत्र की धाक जमाई
- पूरी दुनिया में बढ़ी है इफको के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की मांग
- न्यूनतम कीमत और उच्च गुणवत्ता के मानकों तक पहुंचने में सफल रहा है इफको

हमारी सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) और सहकारी डेयरियों को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पैक्स एवं सभी सहकारी संस्थाओं के कंप्युटरीकरण, नई व्यावसायिक गतिविधियों के साथ पैक्स को जोड़ने और कोऑपरेटिव के जरिए डेयरियों के अर्थतंत्र को समावेशी बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन विचारों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में बीज अनुसंधान केंद्र की नींव रखने के अवसर पर साझा किया। उन्होंने कहा कि इफको ने बीज अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की है। यह बीज अनुसंधान केंद्र हमारी जमीन में उत्पादकता को बढ़ाएगा, उत्पाद को पोषक बनाएगा और हमारे हजारों सालों पुराने बीजों को संरक्षण प्रदान करने का भी काम करेगा। अनुसंधान केंद्र बीजों में इस प्रकार का सुधार करेगा, जिससे खेती में पानी और खाद का उपयोग कम हो।

इफको की कलोल इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान उन्होंने बीज अनुसंधान केंद्र का भूमिपूजन किया और कहा कि भारत वर्तमान में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। इस आत्मनिर्भरता में इफको की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि इफको ने देश के किसानों को फर्टिलाइजर के साथ जोड़ा और फिर फर्टिलाइजर को कोओपरेटिव के साथ जोड़ने का अहम कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जिस बीज अनुसंधान केंद्र की नींव रखी गई है, यह केंद्र हमारे किसानों

की समृद्धि को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा।

श्री शाह ने कहा कि इफको ने अनेक प्रकार के अनुसंधान और विकास के काम किए हैं। इसके साथ ही इफको ने उर्वरकों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के साथ ही उन्हें किसानों के घर-घर तक पहुंचाने संबंधी सभी कार्यों को बेहद कुशलता के साथ पूरा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जब इफको की शताब्दी मनायी जाएगी, तब दुनियाभर की सहकारी संस्थाओं में इफको का रुतबा बढ़ चुका होगा। श्री शाह ने कहा कि जब 50 वर्ष पहले इफको की नींव डाली गई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि इफको यहां तक पहुंचेगा। इफको की पचास वर्ष की गौरवशाली यात्रा यह दिखाती है कि जब कोऑपरेटिव और कोपोरेट संस्कार मिलकर काम करते हैं तो कैसे अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इफको का पचास वर्षों का सफर हमारी खेती, अनाज उत्पादन एवं ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने और किसानों की समृद्धि को समर्पित रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले पचास वर्षों से सौ वर्षों तक की यात्रा में इफको भारतीय खेती को आधुनिक और सबसे ज्यादा उत्पादक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा और देश की खेती की जमीन का संरक्षण करने और पर्यावरण को बचाने के बड़े उद्देश्यों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि इफको का रिकार्ड रहा है कि जो भी काम इसने हाथ में लिया है, उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया है।

इफको ने भारत के कोऑपरेटिव क्षेत्र की विश्व में धाक जमाई

श्री शाह ने कहा कि इफको ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत के कोऑपरेटिव क्षेत्र की धाक जमाई है। इससे इफको के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की पूरी दुनिया में मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब इफको के कलोल के कारखाने का भूमिपूजन हुआ था, उस जमाने में इसे एक बड़ी क्रांति माना गया था। समय के साथ बदलाव, विकास और विस्तार करते हुए इफको ने नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डीएपी आदि के लिए शोध और प्रयोग के माध्यम से उत्पादन भी बढ़ाया है। अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ ही इफको ने किसानों के खेतों तक पहुंच भी बढ़ाई है और शोध एवं अनुसंधान के माध्यम

90 लाख मीट्रिक टन इफको की खाद उत्पादन क्षमता

40 हजार करोड़ रुपए इफको का टर्नओवर

32 सौ करोड़ रुपए का इफको को हुआ मुनाफा

से प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोगों को देश और दुनिया के किसानों की जमीन तक पहुंचाया है।

इफको के कंडला व कलोल (गुजरात), फूलपुर व आंवला (उत्तरप्रदेश) और पारादीप (ओडिशा) इकाइयों में उर्वरकों का उत्पादन होता है, जिसके व्यापक योगदान से भारत खाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया हैं। श्री शाह ने कहा कि वर्तमान समय में इफको की खाद उत्पादन क्षमता 90 लाख मीट्रिक टन है, जिसकी बिक्री से 40 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है और इससे इफको को 32,00 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वर्तमान समय में इफको ने अपनी उत्पादन क्षमता को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि अब पूरी दुनिया में इफको के उत्पाद बेचें जा रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि पिछले पचास सालों में केमिकल फर्टिलाइजर से नैनो फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर तक की यात्रा इफको के तत्वावधान में हुई है। उन्होंने कहा कि जब इफको की स्थापना हुई, तब फर्टिलाइजर में भारत की ध्यान बड़ी मात्रा में उत्पादन पर था। लेकिन, वर्तमान समय में देश का ध्यान ऐसे लक्षित और नियंत्रित ढंग से उर्वरकों के उत्पादन पर है, जिससे पोषक तत्व भी मिलें और हमारी जमीन खराब भी नहीं हो। इफको के नैनो यूरिया व नैनो डीएपी लिक्विड के साथ किसानों को फसलों के लिए अब अन्य उर्वरकों को डालने की जरूरत नहीं है। ■

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को संसद की मंजूरी

सशक्त होगा सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण

सहकारिता क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग होगी पूरी, हर साल आठ लाख लोग यूनिवर्सिटी से होंगे प्रशिक्षित

सहकारी क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व पीएचडी जैसे कोर्स से युवाओं में होगा दक्षता व क्षमता निर्माण

सहकार उदय टीम

सहकारिता का अलग मंत्रालय बनने के करीब साढ़े तीन साल में इस क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के केंद्र सरकार के विभिन्न पहलों से इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों, नवाचार और नई रणनीतियों की मांग बढ़ी है। इसे पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे शिक्षण संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो न सिर्फ सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा दे सके, बल्कि इसके माध्यम से कुशल युवा प्रबंधकों को तैयार कर सहकारी संगठनों की कार्यक्षमता में सुधार को बल मिले। इसी के मद्देनजर देश में पहला केंद्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने की संकल्पना केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की। यह सहकारिता क्षेत्र में कुशल पेशेवरों के आने से पारदर्शिता को बढ़ावा देने, डिजिटल नवाचार के तहत सहकारी प्लेटफार्मों पर अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर सहकारी संस्थानों के निर्माण और नई योजनाओं के विकास के लिए वित्तीय रणनीतियों के सृजन जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सफल बनाने में मददगार भी होगा। इसके लिए संसद के बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025 पेश किया गया और इसे सत्र के दूसरे चरण में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) के परिसर में बनने वाले इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम भारत में सहकारिता की नींव रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों में शुमार त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। जिस गुजरात राज्य सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) को देश और दुनिया अमूल के नाम से जानती है, वह त्रिभुवन दास पटेल के विचारों की ही देन है। विश्वविद्याल के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का शुरूआती प्रावधान किया गया है। विश्वभर में वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में, भारत में सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का यह कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वास्तव में, यह सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार है। यह विश्वविद्यालय कौशल आधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे युवाओं को सहकारी शिक्षा मिलेगी और सहकारिता क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे सहकारी क्षेत्र में समग्र शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के नए अवसर मिलेंगे। सहकारी क्षेत्र में नवीनतम शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाकर यह यूनिवर्सिटी प्रशिक्षित पेशेवरों को तैयार करेगी, जिससे देशभर में सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार आएगा। मानव संसाधन की दक्षता बढ़ने के साथ देशभर में सहकारिता के

क्षेत्र में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों और संस्थागत सुधारों का सशक्त नेटवर्क स्थापित होगा।

संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा, 'यह विधेयक देश में सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी लाएगा। अब सहकारी शिक्षा भारतीय शिक्षा व पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनेगी और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देशभर के प्रशिक्षित युवा सहकारी क्षेत्र को अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और आधुनिक युग के अनुकूल बनाएंगे।'

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री अमित शाह ने कहा, ''त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ सहकारिता क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इस विश्वविद्यालय से प्रति वर्ष आठ लाख लोग प्रशिक्षित होंगे। इसमें शार्ट और लॉन्ग टर्म कोर्स करने वालों के अलावा चंद दिनों या हफ्ते भर तक चलने वाले ट्रेनिंग कोर्स भी शामिल होंगे। इससे पूरे देश को सहकारिता की भावना और आधुनिक शिक्षा से युक्त युवा सहकारी नेतृत्व मिलेगा। कोऑपरेटिव क्षेत्र के विकास और विस्तार को देखते हुए प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत है। यह यूनिवर्सिटी इस जरूरत को पूरा करने का काम करेगी। यहां से डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त युवाओं को सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं और कंपनियों में नौकरी मिलेगी।''

उनके मुताबिक, इस यूनिवर्सिटी से भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भी बड़ा योगदान दे सकेगा। नये युग की सहकारी संस्कृति भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगी। यह आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का माध्यम बनेगा। इसके माध्यम से सहकारी सिद्धांतों व सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा और कोऑपरेटिव क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकी का फायदा मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही अनुसंधान और नवाचार भी बढ़ेंगे, जिससे जमीनी स्तर पर कोऑपरेटिव क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

राज्यसभा में इस बिल पर हुई चर्चा का जवाब केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। उन्होंने कहा, ''सहकारिता क्षेत्र में गतिशीलता लाने और इसके विस्तार के लिए एक संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। कई सहकारी संस्थाओं में कार्य क्षमता की कमी, मैनेजमेंट में अनियमितताएं और तकनीकी संसाधनों के सीमित उपयोग जैसी चुनौतियां हैं जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र का दायरा और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे नए स्वरोजगार और नवाचार के अवसर सृजित होंगे। पैक्स के सचिव से लेकर एपेक्स (शीर्ष) बैंक के एमडी तक, सभी स्तरों पर कार्य कुशलता और अनुशासन के लिए योग्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार, आगामी पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र को लगभग 17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत होगी। इस आवश्यकता को देखते हुए यूनिवर्सिटी की स्थापना की पहल की गई है।''

देश की दूसरी सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था कृभको और अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन-एशिया पेसिफिक के चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। ■

सहकारी क्षेत्र में आएगी नई क्रांतिः डॉ. उदय शंकर अवस्थी

देश और दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने की भारत सरकार की पहल पर कहा, 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का कदम सहकारी समितियों के विकास के लिए ऐतिहासिक है। इससे सहकारी क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसरों को जन्म देगा और सहकारी क्षेत्र को आधुनिक शिक्षा एवं अनुसंधान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।' उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के इस सराहनीय कदम का स्वागत करते हुए कहा कि सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना भारतीय कृषि, किसानों और ग्रामीण विकास के लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे हमारे गांवों को और मजबूती मिलेगी। साथ ही, देशभर में क्षेत्र विशिष्ट स्कूलों की स्थापना से उर्वरक सहकारी समितियों, खासकर इफको को मदद मिलेगी। इससे सहकारी समितियों को उर्वरक सहकारी प्रबंधन और विपणन के क्षेत्र में पेशेवरों की एक नई पीढ़ी मिलेगी। मौजूदा सहकारी कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम एक गेमचेंजर और ऐसा कदम है जो इस पैमाने पर पहले कभी नहीं किया गया था। यह विश्वविद्यालय मौजूदा कर्मचारियों और सहकारी समितियों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण देगा जो इस क्षेत्र के लिए बड़ी संपत्ति होगी।

International Year of Cooperatives 2025 Cooperatives Build a Better World

सहकारिता क्षेत्र की 17 लाख कुशल पेशेवरों की मांग पूरी करेगी यूनिवर्सिटी

- जल्द शुरू होगी पढ़ाई, यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही कोऑपरेटिव से जुड़ेंगे युवा
- डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी, मैनेजमेंट आदि के होंगे कोर्स

सहकार उदय टीम

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025 पारित हो गया। इसके साथ ही देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया। देश के सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण की दिशा में यह बहुत बड़ा सुधार है। यूनिवर्सिटी बनने के बाद युवा इस क्षेत्र में भी डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी, मैनेजमेंट आदि कोर्स कर सकेंगे और अपना करियर बना सकेंगे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल के अनुसार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और देश के पहले गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में साढ़े तीन साल के कार्यकाल में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। इन सुधारों की वजह से आने वाले वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 17 लाख कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत होगी। यह यूनिवर्सिटी इस जरूरत को पूरा करने में मददगार साबित होगी।

देश में इस समय 8.40 लाख सहकारी समितियां हैं जिनके 30 करोड़ सदस्य हैं और उनमें 40 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। 'सहकार उदय' से हुई बातचीत में श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, "यूनिवर्सिटी बनाने की बात अमित भाई के दिमाग में आई। देश में सहकारिता का इतना बड़ा स्वरूप है, तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि अलग-अलग तरह के कोर्स के माध्यम से स्किल्ड मैनपावर तैयार किए जाने चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए यही सोच थी कि अगर हमें और आगे जाना है, तो भविष्य की मांग को पूरा करने की तैयारी आज से ही करनी होगी।"

यह यूनिवर्सिटी हब और स्कोप मॉडल पर पूरे देश के लिए काम करेगी। इस मॉडल के माध्यम से किसी भी राज्य में सहकारिता से जुड़े शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं, वहां के शिक्षण-प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट इससे एफिलिएशन ले सकते हैं। इसके अलावा, इसकी खासियत यह भी होगी कि जिस राज्य में इंस्टीट्यूट होगा वहां की प्रांतीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी। पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र में किसी भी पद के लिए, चाहे पैक्स का सचिव हो या अपैक्स बैंक के एमडी हों, सभी तरह के पद के लिए युवाओं को तैयार करना है, तो उसके लिए अलग-अलग कोर्स एवं डिग्री हों, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही, वर्तमान में कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम कर रहे पैक्स के सचिव से लेकर अपैक्स बैंक के एमडी तक सभी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से सभी के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी।

श्री मोहोल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की जो

सहकारी क्षेत्र का हो रहा कायाकल्प

कार्यक्षमता में सुधार
प्रशिक्षित मानव संसाधन से सहकारी संगठनों की बढ़ेगी कार्यक्षमता

डिजिटल नवाचार
डिजिटल सहकारी प्लेटफॉर्म से सहकरी अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा

वैश्विक प्रतिस्पर्धा
अंतरराष्ट्रीय मानकों पर सहकारी संस्थाओं का निर्माण

रणनीतियों का विकास
नई फंडिंग योजनाएं विकसित करने के लिए सहायता

कानूनी मार्गदर्शन
कानूनी चुनौतियों से निपटने में मिलेगी सहायता

विकास लक्ष्यों में सहयोग
सहकारिता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक

परिकल्पना है उसे साकार करने के लिए यूनिवर्सिटी के माध्यम से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्किल्ड मैनपावर का सृजन करने के अलावा कोऑपरेटिव के स्पिरिट को बढ़ावा देने में भी हम सक्षम होंगे। यूनिवर्सिटी ही एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ सकता है। आज अगर देखें तो किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाने या बिजनेस खड़ा करने के लिए कोई न कोई कोर्स उपलब्ध है और उनकी शिक्षा दी जा रही है। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है या अन्य कोई भी क्षेत्र, उनके लिए कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट हैं। ऐसी कोई व्यवस्था कोऑपरेटिव में नहीं थी। यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं का लीडरशिप तैयार करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा।

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से सहकारी कार्यक्षमता, पारदर्शिता, डिजिटल नवाचार, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर संस्थान और नई फंडिंग रणनीतियों जैसे लाभ मिलेंगे। इससे सहकारी संगठनों के सतत विकास को नई दिशा मिलेगी। अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक बनाने और इसका विस्तार करने के लिए करीब पांच दर्जन पहल किए गए हैं। 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना जरूरी है जिसे सहकारिता के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। इसे ध्यान में रख कर ही देश में पहली बार कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से नए लोगों को शिक्षित-प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके माध्यम से सभी के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। सहकारिता क्षेत्र बहुत विशाल है और यह समाज के सभी अंगों से जुड़ा है। सहकारिता से जुड़े लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देकर सहकारी आंदोलन को और मजबूत किया जा सकता है। यह

> केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में साढ़े तीन साल के कार्यकाल में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। इन सुधारों की वजह से आने वाले वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 17 लाख कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत होगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इस जरूरत को पूरा करने में मददगार साबित होगी।
>
> **- श्री मुरलीधर मोहोल**
> **केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री**

सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने और इसका विस्तार करने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर की गई इस पहल से अंतरराष्ट्रीय सहकारी क्षेत्र में भारत की साख और बढ़ेगी।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री मोहोल ने बताया कि जल्द से जल्द यहां पढ़ाई और प्रशिक्षण शुरू हो जाए इसका प्रयास सरकार कर रही है। आणंद के इरमा में सब स्ट्रक्चर तैयार है। वहां पर फैकेल्टी भी तैयार हैं और गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी तैयार हैं। बहुत जल्द यूनिवर्सिटी शुरू किया जाएगा और उसके बाद पूरे देश में उसका विस्तार भी हो जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के महानिदेशक श्री जेरोन डगलस ने कहा कि यह एक ऐसा कदम है जो न केवल भारतीय सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा, बल्कि ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक सहकारी आंदोलन में आधारशिला के रूप में कार्य करेगा और इसकी ताकत बढ़ाएगा। ■

International Year of Cooperatives 2025

रामेश्वरम में नए पंबन पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विकास में महत्वपूर्ण होगी नीली अर्थव्यवस्था

सहकार उदय टीम

- पांच वर्ष में तमिलनाडु को पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मिली पर्याप्त धनराशि, मछुआरों को मिल रही आधुनिक सुविधाएं
- तमिलनाडु को मिली 8,300 करोड़ रुपए की सौगात, रेल एवं सड़क की विभिन्न परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस क्षेत्र में तमिलनाडु की ताकत को वैश्विक स्तर पर पहचाना जाएगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण मौके पर उन्होंने यह बात कही। भारत के लंबे समुद्र तटीय इलाके और जमीन पर विशाल जल क्षेत्र को देखते हुए मत्स्य क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। समुद्री मछुआरों के जीवन में सुधार लाने और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। पिछले पांच वर्ष में तमिलनाडु को पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत पर्याप्त धनराशि मिली है, जिससे मछुआरों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया जा रहा है। इसमें समुद्री शैवाल पार्क, मछली पकड़ने के बंदरगाह और लैंडिंग केंद्रों में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। पिछले एक दशक में श्रीलंका से 3,700 से अधिक मछुआरों को वापस लाया गया है, जिनमें से 600 से अधिक को पिछले वर्ष ही लाया गया।

रामेश्वरम में उन्होंने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज- पंबन पुल का उद्घाटन किया और सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाकर पुल का संचालन देखा। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसे 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 2.08 किमी है जिसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठता है। इससे जहाजों की सुचारू आवाजाही और निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित होता है। इसे भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए दोहरी रेल पटरियों के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि रामनवमी के विशेष दिन पर उन्हें 8,3000

करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को सौंपने का अवसर मिला। ये रेल और सड़क परियोजनाएं तमिलनाडु में कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देंगी। राज्य के लिए ये परिवर्तनकारी पहल हैं।

पिछले 10 वर्ष में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा, ''पिछले 10 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो गया है। इस वृद्धि का एक प्रमुख कारण देश का उल्लेखनीय आधुनिक बुनियादी ढांचा है। पिछले एक दशक में रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली, पानी और गैस पाइपलाइन जैसे बुनियादी ढांचे के लिए बजट में लगभग छह गुना वृद्धि हुई है। आज देश भर में मेगा प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जब भारत का हर क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ता है, तो विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग मजबूत होता है।'' जैसे-जैसे भारत का हर राज्य जुड़ता है, देश की पूरी क्षमता का अहसास होता है।

भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में तमिलनाडु की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे तमिलनाडु की क्षमता बढ़ती जाएगी, भारत का विकास और भी तेज होगा। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने 2014 से पहले की अवधि की तुलना में तमिलनाडु के विकास के लिए तीन गुना अधिक धनराशि आवंटित की है, जिसने तमिलनाडु के आर्थिक और औद्योगिक विकास में बहुत योगदान दिया है। तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है। पिछले एक दशक में तमिलनाडु का रेल बजट सात गुना से अधिक बढ़ा है। 2014 से पहले तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं को सालाना केवल 900 करोड़ रुपए मिलते थे, जबकि इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत सरकार राज्य के 77 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रही है, जिसमें रामेश्वरम स्टेशन भी शामिल है।

ग्रामीण सड़कों और राजमार्गों के विकास में हुई उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2014 से केंद्र सरकार के सहयोग से तमिलनाडु में 4,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। चेन्नई पोर्ट को जोड़ने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर उल्लेखनीय बुनियादी ढांचे का एक और उदाहरण होगा।

चेन्नई मेट्रो जैसी आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां तमिलनाडु में यात्रा को आसान बना रही हैं। पिछले दशक के दौरान भारत में सामाजिक बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु में बनाए गए 12 लाख से अधिक पक्के मकान शामिल हैं। लगभग 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पहली बार पाइप से पीने का पानी मिला है। इनमें तमिलनाडु के 1.11 करोड़ परिवार शामिल हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत तमिलनाडु के छोटे किसानों को लगभग 12,000 करोड़ रुपए मिले हैं। साथ ही, पीएम फसल बीमा योजना से भी लाभ मिला है जिसके तहत 14,800 करोड़ रुपए के दावे किए गए हैं।

नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता में है। आयुष्मान भारत योजना के तहत तमिलनाडु में 1 करोड़ से अधिक लोगों का उपचार किया गया है जिससे राज्य के परिवारों का 8,000 करोड़ रुपए का खर्च बचा है। तमिलनाडु में 1,400 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं जहां 80 प्रतिशत तक की छूट पर दवाइयां उपलब्ध हैं। इन सस्ती दवाओं के कारण राज्य के लोगों को 700 करोड़ रुपए की बचत हुई है। नरेन्द्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि युवा भारतीयों को डॉक्टर बनने के लिए विदेश न जाना पड़े। इसके लिए हाल के वर्षों में तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु सरकार से तमिल भाषा में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को मदद मिल सके। ■

पंबन पुल प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिलन का प्रतीक

प्रधानमंत्री ने कहा, "रामेश्वरम के लिए नया पंबन पुल प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिलन का प्रतीक है। हजारों साल पुराना एक शहर अब 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार से जुड़ गया है। यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो बड़े जहाजों को नीचे से गुजरने की अनुमति देता है और साथ ही तेज ट्रेन यात्रा को सक्षम बनाता है। इस पुल की मांग कई दशकों से हो रही थी। पंबन पुल व्यापार और यात्रा में सुगमता लाएगा जिससे लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे तमिलनाडु में व्यापार और पर्यटन को लाभ होगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।" श्री मोदी ने रामेश्वरम से तांबरम (चेन्नई) तक की एक नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया।

जीसीसीआई के ट्रेड एक्सपो 2025 में बोले श्री अमित शाह

ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत

सहकार उदय टीम

- प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अनेक प्रकार की व्यवस्था और विकास में आगे बढ़ा है
- ग्लोबल इकोनॉमी का गेटवे और अनेक क्षेत्रों में पायनियर बनकर देश के विकास में बड़ा योगदान कर रहा गुजरात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले करीब 11 सालों में भारत 'विश्व गुरु' बनने की दिशा में आगे बढ़ा है और देश के हर क्षेत्र में अनेक प्रकार की व्यवस्था एवं विकास का सूत्रपात हुआ है। इन वर्षों में भारत ने पूरी तरह से बहुआयामी और संपूर्ण सहकारी दृष्टिकोण के कारण कई उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन तथ्यों को गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) के वार्षिक ट्रेड एक्सपो 2025 के शुभारंभ के दौरान दोहराया। उन्होंने कहा कि देश में गुजरात अब उन सारे क्षेत्रों में पायनियर बन गया है, जो आगामी 25 वर्षों की वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्णय करेंगे। श्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने कई क्षेत्रों में पूरे देश में नई शुरुआत की है। सबसे पहले स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की परिकल्पना गुजरात में हुई और गांवों में चौबीस घंटे बिजली मिलने की शुरुआत भी यहीं हुई। इस राज्य ने ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनने की दिशा में सबसे पहले पहल की है। वर्ष 2009 में ई-ग्राम प्रोजेक्ट की शुरुआत गुजरात ने की और इंटर-कनेक्टिविटी एवं डिजिटल सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने की शुरुआत भी यहीं हुई। मातृ मृत्युदर को कम करने की दिशा में गुजरात ने ही पहल की। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात के कच्छ में बना और सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड

समय की जरूरतों को पूरा करे व्यापारिक संगठन

श्री शाह ने कहा कि आने वाले समय में अगर चैम्बर को प्रासंगिक रहना है तो कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ साथ इसमें उद्योगों, औद्योगिक क्षेत्र में कदम रखने वाले साहसी युवाओं, उद्योगपतियों, इन तीनों को मदद करने के लिए एक स्थायी तंत्र बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चैम्बर के पदाधिकारी ऐसे पेशेवर लोगों के साथ एक तंत्र बनाएं, तो अगले 25 वर्षों में भी चैम्बर की प्रासंगिकता और महत्ता और बढ़ेगी। श्री शाह ने कहा कि जीसीसीआई सरकार व नए उद्योगपतियों, सरकार व युवाओं और सरकार एवं विकास करने की इच्छा रखनेवाले उद्योगपतियों के बीच सेतु बनने का कार्य भी सरलता से पूरा करके अपनी भूमिका और प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है।

गुजरात के विकास में जीसीसीआई का अहम योगदान

चैम्बर ने युवाओं में उद्यम, साहस और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर व्यापार करने का उत्साह भरने का काम किया है। लगातार 75 वर्षों तक चैम्बर ने उस परंपरा को संभाला है, सरकार के साथ संवाद बनाए रखा है और जनता के हित की चिंता करते हुए प्राकृतिक आपदाओं के समय जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। श्री शाह ने कहा कि 75 वर्षों पहले शेठ कस्तूरभाई लाल भाई एवं शेठ अमृतलाल हरगोविंदास के नेतृत्व में जीसीसीआई की नींव रखी गई थी और तबसे इसने गुजरात के विकास में बेहद अहम योगदान दिया है। इस चैम्बर के नेतृत्व को अब संस्था के 75 वर्ष से 100 वर्ष का रोडमैप तैयार करना चाहिए, जिससे गुजरात के विकास में अधिकतम योगदान करते हुए यह और आगे बढ़े।

सरकार, लघु उद्योग व युवाओं के बीच सेतु बने जीसीसीआई

श्री शाह ने कहा कि गुजरात के युवाओं की औद्योगिक साहसिकता के गुण को और प्रोत्साहन मिले, इसके लिए चैम्बर को योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और अगर देखें तो किसी भी उद्योग ने सालों पहले एक लघु उद्योग के रूप में ही शुरुआत की होगी। श्री शाह ने कहा कि गुजरात के लघु उद्योगों ने देश के औद्योगिक विकास में बहुत अच्छा योगदान दिया है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज को लघु उद्योगों की परंपरा को स्टार्टअप के साथ जोड़कर और उसे आधुनिक बनाकर, हमारे युवाओं के लिए एक संपूर्ण तंत्र उपलब्ध कराना चाहिए और इसे सरकार, लघु उद्योग और साहसिक युवाओं के बीच सेतु बनने का काम करना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि जीसीसीआई गुजरात का विजन 'ग्लोबल एंबिशन' सूत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। जीसीसीआई के इस एक्सपो में विभिन्न क्षेत्रों और नवाचारों से जुड़े 300 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वर्ष 1949 से काम शुरू किया था और तब से अब तक इसने गुजरात के विकास में अपूर्व योगदान किया है। उन्होंने कहा कि चैम्बर के साथ 75 से अधिक संस्थाएं और ढाई लाख से अधिक छोटे औद्योगिक संगठन जुड़े हुए हैं। इस चैम्बर ने 'ग्रो बिजनेस एन्ड ट्रान्सफॉर्म गुजरात' के सूत्र को चरितार्थ करने के लिए परिश्रम करके सरकार के साथ बेहतरीन संवाद स्थापित किया है। उन्होंने वायब्रेंट गुजरात की ग्लोबल सफलता में भी चैम्बर की बड़ी भूमिका बताई और कहा कि वर्ष 2001 से 2025 तक भूकंप की त्रासदी से लेकर पायनियर इंडस्ट्रीज का हब बनने वाले गुजरात की यात्रा में चैम्बर की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

सिटी भी धोलेरा स्मार्ट सिटी के रूप में गुजरात में स्थापित हो रही है। देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे सूरत-चेन्नई एक्सप्रेस-वे इसी राज्य से शुरू हुआ है। श्री शाह ने कहा कि गिफ्ट सिटी के रूप में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हब भी गुजरात में ही बना और पहली बुलेट ट्रेन भी गुजरात से ही शुरू हुई। उन्होंने कहा कि पहली नमो भारत रैपिड रेल भी गुजरात से ही है। राज्य ने एक मजबूत औद्योगिक विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और उद्योग-अनुकूल सरकार के दृष्टिकोण को साकार किया है।

अनुकूल औद्योगिक वातावरण से हो रहा बदलाव

श्री शाह ने कहा कि गुजरात में उद्योग से लेकर तकनीक, आईटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई से स्टार्टअप एवं 'पायनियर इंडस्ट्रीज' तक हर प्रकार के उद्योगों का एक प्रकार से सुंदर औद्योगिक वातावरण देखा जा सकता है। गुजरात में उद्योग लगाने में रुचि रखने वाले लोगों को पता है कि राज्य में उन्हें बिना किसी राजनीतिक दखल के सुविधा और इंडस्ट्री के अनुकूल वातावरण और बिना हड़ताल वाला तंत्र मौजूद है। इस परंपरा को श्री भूपेन्द्र पटेल की राज्य सरकार दृढ़ता से प्रस्थापित कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि जब श्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात सरकार जीसीसीआई के साथ सार्थक चर्चा करके और व्यापारियों, उद्योगपतियों और लघु उद्यमियों की बातें सुनकर ही अंतिम निर्णय लेती थी। श्री शाह ने कहा कि तबसे लेकर वर्तमान समय की राज्य सरकार उस वातावरण को और मजबूत करने में योगदान कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने उस समय नीति बनाई थी कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अर्थव्यवस्था की मजबूती से हर नागरिक के जीवन में सुविधाएं अपने आप जुड़ जाएंगी। श्री शाह ने कहा कि इसी कारण गुजरात अब ग्लोबल इकोनॉमी का गेटवे बनकर देश के विकास में बड़ा योगदान कर रहा है। ■

नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के शिलान्यास पर बोले प्रधानमंत्री

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता

सहकार उदय टीम

सभी नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है ताकि सबसे गरीब व्यक्ति को भी सर्वोत्तम संभव उपचार मिल सके। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से मुफ्त इलाज और जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाना इसी दिशा में किया जा रहा प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नींव रखने के अवसर पर यह बात कही।

नागपुर स्थित माधव नेत्रालय दशकों से लाखों लोगों की सेवा कर रहा है और अनगिनत लोगों के जीवन में रोशनी लौटा चुका है। अब इसका विस्तार करने के लिए नया परिसर बनाया जा रहा है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने विश्वास जताया कि यह विस्तार इसके सेवा कार्यों को और तेज करेगा जिससे हजारों नए जीवन में रोशनी आएगी और उनके जीवन से अंधकार दूर होगा। उन्होंने माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की और भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालते हुए माधव नेत्रालय के प्रयासों को इनका पूरक बताया।

प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोगों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं ने लोगों को चिकित्सा जांचों के लिए लंबी यात्रा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

- आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र के माध्यम से कम आय वाले हो रहे लाभान्वित
- माधव नेत्रालय का विस्तार करने के लिए बनाया जा रहा नया परिसर

देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी करने और एम्स की संख्या तीन गुनी करने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में अधिक कुशल डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल सीटों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई है। मेडिकल

छात्रों को उनकी मूल भाषाओं में चिकित्सा का अध्ययन करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के साथ-साथ देश अपने पारंपरिक ज्ञान को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने भारत के योग और आयुर्वेद को मिल रही वैश्विक मान्यता पर कहा कि ये विश्व मंच पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं।

माधव नेत्रालय के नए परिसर की यात्रा शुरू होने पर दृष्टि और दिशा के बीच स्वाभाविक संबंध पर टिप्पणी करते हुए श्री मोदी ने वैदिक आकांक्षा ''पश्येम शरदः शतम्'' जिसका अर्थ है ''हम सौ वर्षों तक देख सकें', का उल्लेख करते हुए जीवन में दृष्टि के महत्व के बारे में बताया। ऐसी दृष्टि व्यक्ति और समाज दोनों को सशक्त बनाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पवित्र प्रयास है जो बाह्य और आंतरिक दोनों दृष्टियों की दिशा में काम कर रहा है।'' उन्होंने माधव नेत्रालय को बाह्य दृष्टि का और संघ को आंतरिक दृष्टि का उदाहरण बताया जिसने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है।

प्रधानमंत्री ने शास्त्रों का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जीवन का उद्देश्य सेवा और परोपकार है। जब सेवा मूल्यों में समाहित हो जाती है तो यह भक्ति बन जाती है। जीवन का महत्व इसकी अवधि में नहीं, बल्कि इसकी उपयोगिता में निहित है। प्रधानमंत्री ने ''मैं'' की बजाय ''हम'' को प्राथमिकता देने और सभी नीतियों और निर्णयों में राष्ट्र को पहले स्थान पर रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण से पूरे देश में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। उन्होंने देश को पीछे धकेलने वाली जंजीरों को तोड़ने की आवश्यकता और औपनिवेशिक मानसिकता से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया।

> "किसी भी नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, उन्हें चिकित्सा उपचार के बारे में चिंतित नहीं रहना चाहिए। आयुष्मान भारत ने लाखों लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया है।"
>
> **- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

श्री मोदी ने कहा, ''भारत का मार्गदर्शक सिद्धांत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है और भारत के कार्यों में इसकी झलक मिल रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने दुनिया को एक परिवार के रूप में टीके उपलब्ध कराए। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप, तुर्की और नेपाल में भूकंप और मालदीव में जल संकट के दौरान त्वरित सहायता उपलब्ध करवाई। युद्धों के दौरान अन्य देशों के नागरिकों को निकालने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक भाईचारे की यह भावना भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से उपजी है।'' भारत के युवाओं को देश की सबसे बड़ी संपत्ति, आत्मविश्वास से भरपूर और जोखिम उठाने की बढ़ी हुई क्षमता के रूप में रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने नवाचार, स्टार्टअप और भारत की विरासत और संस्कृति में उनके योगदान का उल्लेख किया। ■

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ दिवस की परेड में बोले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन को देख नक्सलियों की कांप जाती है रूह

सहकार उदय टीम

➲ देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ की रहेगी सबसे बड़ी भूमिका

➲ आगामी 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस पर आयोजित परेड में हिस्सा लेने के बाद पूरे विश्वास के साथ कहा कि सरकार देश को नक्सल मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। आगामी वर्ष 2026 में 31 मार्च से पहले देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। सीआरपीएफ जवानों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कोबरा बटालियन को देख नक्सलियों की रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के समूल नाश में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद फिर से जड़ न जमा पाए, इसलिए इसका समूल नाश आवश्यक है, क्योंकि नक्सलवाद के कारण कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद 31 मार्च, 2026 से पहले ही एक इतिहास बन जाएगा। श्री शाह ने दूसरे राज्यों में भाग रहे नक्सलियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों में और बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचाने के लिए बनाई गई 'नियद नेल्लानार' को सुरक्षा बलों के शिविरों के पांच किलोमीटर के दायरे से बढ़ाकर 10 किलोमीटर करने को निर्देशित किया, जिससे जनता को विकास के समान अवसर सुनिश्चित हो सके।

बस्तर विकास, विश्वास और विजय की लौ के साथ आगे बढ़ रहा है। बस्तर अब भय नहीं, बल्कि भविष्य का पर्याय बन चुका है और अब यहां नक्सलवाद के साथ कोई नहीं जुड़ता। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे बस्तर का विकास और निर्माण करना है जिससे इस अंचल के सुकमा से युवा इंस्पेक्टर बनें, बस्तर से बैरिस्टर, दंतेवाड़ा से डॉक्टर और कांकेर से होनहार कलेक्टर बनें। श्री शाह ने स्थानीय लोगों का आह्वान किया कि विकास के सपनों को सच करने के लिए सभी निष्ठापूर्वक और निर्भीक होकर प्रयास करें, क्योंकि मोदी सरकार में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग यह समझ गए हैं कि विकास के लिए हाथ में बंदूक नहीं, कंप्यूटर चाहिए, हथगोला नहीं, बल्कि कलम चाहिए, उन सबने सरेंडर कर दिया है। नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में इस साल अब तक 521 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है जबकि पिछले वर्ष 2024 में कुल 881 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था।

नक्सलियों के आतंक के कारण पहले राजनेताओं को रैली और सभा करने से रोक लिया जाता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज वे 50 हजार आदिवासी भाई बहनों के सामने बस्तर पंडुम महोत्सव मना रहे हैं। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां अब मशीनों की आवाजें आती हैं, जहां गांव वीरान थे, अब वहां स्कूलों की घंटियां बजती हैं, जहां पहले सड़क एक स्वप्न होता था, वहां राजमार्ग बन रहे हैं और जहां बच्चा स्कूल जाने से डरता था आज वहां का बच्चा कंप्युटर के माध्यम से पूरे विश्व के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है।

उभरता भारत शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

सहकार उदय टीम

➲ भारत ने तेज गति से बढ़कर अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना कर लिया

➲ 10 हजार नए पीएम रिसर्च फेलोशिप से आसान होगी युवाओं की यात्रा

दुनिया की नजर भारत पर है और दुनिया की उम्मीदें भी भारत से हैं। कुछ ही वर्षों में भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अनेक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत दोगुनी गति से आगे बढ़ा है और केवल एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना कर लिया है। इन तथ्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 'उभरता भारत शिखर सम्मेलन' में व्यक्त किया। उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह अभूतपूर्व वृद्धि भारतीय युवाओं की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है। श्री मोदी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं के सपनों, दृढ़ संकल्प और जुनून का जिक्र कर 2047 तक भारत की प्रगति के रोडमैप पर जोर दिया और कहा कि निरंतर विचार-विमर्श से विकास की बहुमूल्य अंतरदृष्टि प्राप्त होगी, जो अमृत काल की पीढ़ी को ऊर्जा, मार्गदर्शन और गति प्रदान करेगा।

भारत अपनी प्रगति में अजेय, अटल और अविचल है

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने नए वर्ष के पहले सौ दिनों में देश के युवाओं की आकांक्षाओं और भविष्य की नींव रखने वाले फैसले किए हैं। युवा पेशेवरों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाने वाली 12 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स सहित बहुत से पहल किए गए हैं। शिक्षा के विस्तार के तहत 10 हजार नई मेडिकल सीटें और 6,500 नई आईआईटी सीटें जोड़ी गई हैं और 50 हजार नई अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना नवाचारों की देश के हर कोने तक पहुंच को सुनिश्चित कर रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) और कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के निर्माण का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये युवाओं को भविष्य के लिए तैयार होने के अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने 10 हजार नए पीएम रिसर्च फेलोशिप की भी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला गया था, उसी तरह अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को भी खोला जाएगा, जिससे सीमाएं हटेंगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। संविदा अर्थव्यवस्था (गिग इकोनॉमी) में कार्यरत युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत का जिक्र किया। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण पर जोर दिया और कहा कि समावेशिता अब सिर्फ वादा नहीं है, बल्कि एक नीति है। इन फैसलों से भारत के युवाओं को सीधा फायदा होगा। पिछले सौ दिनों की उपलब्धियां दर्शाती हैं कि भारत अपनी प्रगति में अजेय, अटल और अविचल है।

श्री मोदी ने 10 हजार लाख टन के रिकॉर्ड कोयला उत्पादन और राष्ट्रीय खनिज मिशन के शुभारंभ का जिक्र कर कहा कि कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की स्थापना की गई। उन्होंने किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि के निर्णय को किसानों के कल्याण हेतु सरकार की प्राथमिकता कहा। छत्तीसगढ़ में तीन लाख से अधिक परिवारों का सामूहिक गृह प्रवेश हुआ और स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। इन्हीं दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंगों में शामिल सोनमर्ग सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई। भारतीय नौसेना में आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वाग्शीर को शामिल किया गया और सेना के लिए 'मेड इन इंडिया' हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी गई।■

International Year of Cooperatives 2025

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर संसद में हुई चर्चा में बोले श्री अमित शाह

वक्फ की घोषणा मात्र से किसी की जमीन पर कोई नहीं कर पाएगा कब्जा

सहकार उदय टीम

संसद से पारित वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में धार्मिक दान से जुड़े कार्यों में किसी गैर-इस्लामिक सदस्य को जगह नहीं मिलेगी। वक्फ बोर्ड में जिन गैर-मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा। चैरिटी कमिश्नर किसी भी धर्म का व्यक्ति बन सकता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड का संचालन चैरिटी कानून के मुताबिक हो, यह धर्म का नहीं, प्रशासन का काम है। लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उक्त बातें स्पष्ट की। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक अब कानून बनकर पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से जुड़े ट्रस्ट यानि वक्फ में सरकार कोई दखल नहीं करना चाहती। मुतवली, वाकिफ, वक्फ सब मुस्लिम ही होंगे, परन्तु यह जरूर देखा जाएगा कि वक्फ की संपत्ति का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं। 2013 में अगर वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया गया होता, तो यह विधेयक लाने की नौबत ही नहीं आती। तब रातों रात दिल्ली में लुटियन्स जोन की 123 वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई। उन्होंने बताया कि 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिसमें 2013 से 2025 तक और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। लीज पर दी गई संपत्तियां 20 हजार थीं, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य हो गईं। ये संपत्तियां बेच दी गईं।

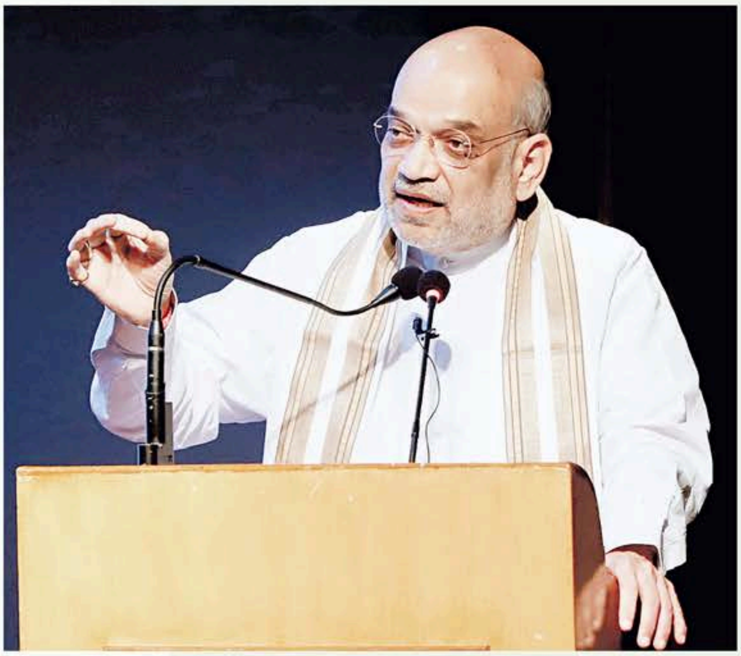

- वक्फ बोर्ड के गैर-मुस्लिम सदस्यों का काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा
- अब किसी की जमीन घोषणा मात्र से ही वक्फ की नहीं हो जाएगी, केवल अपनी संपत्ति ही कर सकेंगे दान

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर करते ही कानून बन गया। अब यह वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 हो गया है जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। यह कानून 8 अप्रैल, 2025 से पूरे देश में लागू हो गया है। यह कानून जमीन की सुरक्षा प्रदान करेगा। अब किसी की जमीन घोषणा मात्र से ही वक्फ की नहीं हो जाएगी। इसके तहत दान केवल अपनी संपत्ति का ही किया जा सकता है, सरकारी या किसी और की संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता। इस कानून में वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार को

सामाजिक न्याय के नए युग का प्रारंभः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से सामाजिक न्याय के नए युग का प्रारंभ होगा। संसद के दोनों सदनों से वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पारित होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, "संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने लाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है।" प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी नजर आ रही थी। इससे मुख्य रूप से हमारी मुस्लिम माताओं-बहनों, गरीब और पसमांदा मुसलमान भाई-बहनों के हितों को बहुत नुकसान हो रहा था। अब संसद द्वारा पारित विधेयक पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा में भी मददगार बनेगा। इसके साथ ही हम एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जो आज के समय के अनुरूप होने के साथ ही सामाजिक न्याय को लेकर प्रतिबद्ध होगा। देश के हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यह मार्ग ज्यादा सशक्त, समावेशी और संवेदनशील भारत के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।

समाप्त कर दिया गया है। अब इसे कलेक्टर से सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नए वक्फ का पारदर्शी तरीके से पंजीकरण भी करवाना होगा। अब मुस्लिम भी वक्फ ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत अपना ट्रस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए वक्फ कानून जरूरी नहीं है। इस कानून के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया जिसकी 38 बैठकें हुईं और 113 घंटे तक इस पर चर्चा हुई। इसके 284 हितधारक बनाए गए जिनके माध्यम से देशभर से लगभग एक करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। उन सुझावों पर विचार कर ही यह कानून बनाया गया।

चर्चा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन में गैर-मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान नहीं है। सरकार ऐसे प्रावधान करना भी नहीं चाहती। विपक्ष द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में दखल के लिए लाया जा रहा। वक्फ बोर्ड या इसके परिसरों में जिन गैर-मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा, उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा। वे सिर्फ यह सुनिश्चित करेंगे कि दान से संबंधित मामलों का प्रशासन नियम के अनुरूप चल रहा है या नहीं। श्री शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वालों को पकड़ कर बाहर निकालने का होना चाहिए। उसे ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने वक्फ के नाम पर औने-पौने दाम में संपत्तियों को सौ-सौ साल तक किराए पर दे रखा है। वक्फ के पैसे से अल्पसंख्यक समुदाय का विकास होना चाहिए और इस्लाम धर्म की संस्थाओं को पुख्ता किया जाना चाहिए। इस पैसे की चोरी पर रोक लगाना ही वक्फ बोर्ड और उसके परिसर का काम होगा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तर रेलवे की भूमि वक्फ के नाम कर दी। वहीं, हिमाचल प्रदेश में वक्फ की संपत्ति बता कर उस जमीन पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया गया। तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदूर मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक की एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 29,000 एकड़ वक्फ भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दे दी गई। वर्ष 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की वक्फ संपत्ति निजी संस्थानों को 100 साल की लीज पर सौंप दी गई। इस मामले में बेंगलुरु हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद 602 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को रोका गया। विजयपुर, कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि को विवादित बनाकर 500 करोड़ रुपए मूल्य की इस जमीन को फाइव स्टार होटल को मात्र 12,000 रुपए प्रति माह के किराए पर दे दिया गया। श्री अमित शाह ने कहा कि यह सारा पैसा गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए है, न कि धनकुबेरों की लूट के लिए। यह पैसा गरीब मुसलमानों, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथ बच्चों, बेरोजगार मुसलमानों के भलाई और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास लाखों करोड़ों रुपए की भूमि है, लेकिन आय सिर्फ 126 करोड़ रुपए है।

वक्फ बोर्ड द्वारा कर्नाटक में दत्तापीठ मंदिर पर दावा किया गया। तालीपरंबा में 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ भूमि पर कब्जे की कोशिश की गई। ईसाई समुदाय की संपत्तियों पर भी कब्जा किया गया। तेलंगाना में 66 हजार करोड़ रुपए की 1700 एकड़ जमीन पर और असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा किया गया। गुरुद्वारे से संबंधित हरियाणा की चौदह मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। महाराष्ट्र के वडांगे गांव में महादेव के मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। ■

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से सहकारिता का भविष्य होगा उज्ज्वल

श्री दिलीप संघाणी

भारत में सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। विधेयक के संसद से दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाने से अब यह सपना साकार हो चुका है। यह विश्वविद्यालय न केवल सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि सहकारी क्षेत्र को अधिक पेशेवर व प्रभावी बनाने में भी मदद करेगा और सहकारी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। यह संस्थान सहकारी शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिससे सहकारी संस्थानों का कार्य अधिक पेशेवर, आधुनिक और प्रभावी हो सकेगा। यह युवाओं को एक वैकल्पिक और आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को सहकारी संस्थाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे यह एक आकर्षक करियर विकल्प बनेगा।

सहकारी क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा देकर यह विश्वविद्यालय युवाओं को सहकारी प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, सहकारी विपणन, डिजिटल सहकारिता और अन्य विषयों में विशेष शिक्षा प्रदान करेगा। पेशेवर प्रशिक्षण और नवीनतम शोध के माध्यम से सहकारी समितियों को

अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा। डिजिटल तकनीकों, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से सहकारी संस्थानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी कर भारतीय सहकारी क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा।

सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण

सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए शोध और प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों और देशों में सहकारी नीतियों का अध्ययन कर भारत के लिए उपयुक्त सहकारी नीतियों पर अनुसंधान करेगा। सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और प्रबंधकों के लिए समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

सहकारी संगठनों को पर्यावरण हितैषी नीतियों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे सतत विकास को बल मिलेगा।

इस प्रकार, यह विश्वविद्यालय भारत में सहकारी आंदोलन को स्वर्णिम युग में ले जाने वाला एक ऐतिहासिक संस्थान साबित होगा, जो 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारी क्षेत्र की भूमिका को प्रभावी बनाएगा।

–अध्यक्ष, इफको

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान होगा। इसके पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख होंगे, जिनमें शामिल होंगेः

सहकारी प्रबंधन : सहकारी संस्थानों के सुचारू संचालन और नेतृत्व कौशल।

सहकारी वित्त : सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए पेशेवर ट्रेनिंग।

डिजिटल सहकारिता : सहकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का समावेश।

सामुदायिक विकास और सहकारिता : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना।

कृषि और ग्रामीण सहकारिता : कृषि आधारित सहकारी समितियों को आधुनिक बनाने के लिए।

सहकारी आंदोलन और 'विकसित भारत' का लक्ष्य

भारत सरकार 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। सहकारी क्षेत्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित तरीकों से योगदान देगाः

आत्मनिर्भर भारतः सहकारी समितियां स्थानीय स्तर पर उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी।

रोजगार सृजनः सहकारी क्षेत्र के विस्तार से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

कृषि क्षेत्र में क्रांतिः कृषि सहकारी समितियों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जाएगी।

वित्तीय समावेशनः सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटीज ग्रामीण भारत को वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी।

श्रीलाल शुक्ल जन्मशती उत्सव में बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल

सहकारी संस्था इफको की प्राथमिकताओं में साहित्य व संस्कृति भी शामिल

सहकार उदय टीम

पद्म भूषण से सम्मानित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और व्यंग्यकार श्रीलाल शुक्ल का जन्मशती उत्सव लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। देश और दुनिया की नंबर वन कोऑपरेटिव इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) के भाषा, साहित्य एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से इस उत्सव का आयोजन किया गया। 31 दिसंबर, 1925 को जन्मे श्रीलाल शुक्ल की जयंती का यह सौवां साल है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा किया गया।

जन्मशती उत्सव के दौरान विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं पर चर्चा की गई, उनका पाठ, नाटक का मंचन और उनकी जीवनी पर बनी एक लघु फिल्म को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा ने साहित्य में श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं के अभूतपूर्व योगदान को याद करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को बताया। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र की प्रमुख संस्था इफको की प्राथमिकताओं में साहित्य, कला और संस्कृति भी शामिल है।

कार्यक्रम के पहले सत्र में चित्र और पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। इस सत्र में अभिनेता पंकज त्रिपाठी और अशोक पाठक द्वारा किया गया एक मन लुभावन अंश पाठ ने श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी के किरदारों को जीवंत रूप प्रदान कर दिया। दूसरे सत्र 'श्रीलाल शुक्ल : कुछ रंग, कुछ राग' में वरिष्ठ लेखक श्री महेंद्र भीष्म ने अपने विशेष अंदाज में श्रीलाल शुक्ल की रचना यात्रा से दर्शकों को अवगत करवाया।

लखनऊ में आयोजित उत्सव में श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं पर चर्चा, इफको अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी व एमडी डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने विचार व्यक्त किए

उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारी मंत्री जे.पी. एस. राठौर ने इस सत्र में अपने विचार प्रकट करते हुए अपने जीवन में साहित्य और श्रीलाल शुक्ल से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया।

तीसरा सत्र 'राग दरबारी : कल आज और कल' में किस्सागो हिमांशु वाजपेयी, साहित्यकार डॉ. जयप्रकाश कर्दम तथा दैनिक जागरण राज्य संपादक आशुतोष शुक्ल ने आधुनिक जीवन में राग दरबारी की प्रासंगिकता पर एक व्यापक विचार-विमर्श प्रस्तुत किया। इस सत्र की अध्यक्षता इफको के अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में उनकी रचनाओं को 'सत्य का उद्घोष' बताया। चौथे सत्र में श्रीलाल शुक्ल के जीवन और कर्म पर कवि-फिल्मकार श्री देवी प्रसाद मिश्र द्वारा बनाई गई लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस सत्र में लोकगायिका मालिनी अवस्थी और इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने संयुक्त रूप से श्रीलाल शुक्ल के जीवन एवं रचना कर्म पर प्रकाश डाला। मालिनी अवस्थी ने डॉ. अवस्थी के निर्देशन में इफको के साहित्यिक सरोकारों की आत्मीय प्रशंसा की। इस क्रम में उन्होंने लोक जीवन से संबद्ध अपनी सुप्रसिद्ध लोक गीतों जैसे- रेलिया बैरन पिया को लिए जाये रे, सइयां मिले लरकइयां मैं का करूं आदि के गायन से दर्शक दीर्घा को झूमने पर मजबूर कर दिया। मालिनी अवस्थी ने श्रीलाल शुक्ल के 'मकान' उपन्यास का विशेष जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उसमें वर्णित लोकगीत स्त्री जीवन की दशा पर सशक्त व व्यापक अनुभूति प्रस्तुत करते हैं। उनके द्वारा गाए गए कई लोकगीत उसी समान भावभूमि के हैं, जो श्रीलाल शुक्ल के व्यापक रचना संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं।

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

सहकारिता विश्वविद्यालय से बदलेगा देश

भारत में सहकारिता का यह स्वर्णिम काल है। सहकारिता में अभिरुचि रखने वाले नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता आन्दोलन की गति को तेज कर दिया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने कम समय में ही बहुत कुछ कर दिखाया है जिससे आजादी के बाद से अब तक की तुलना में सहकारिता को लेकर उनका कार्य स्वर्णाक्षरों में अंकित हो रहा है। हाल ही में संसद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 पारित हो गया है, जो निश्चय ही देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगा। लोकसभा में विधेयक पेश करते समय श्री शाह ने कहा भी कि इस विधेयक के पारित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता का विकास होगा, सामाजिक समावेशिता बढ़ेगी और नवाचार तथा अनुसंधान में कई नए मानक स्थापित करने के अवसर भी मिलेंगे। पूरे देश को सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व मिलेगा। आजादी के 75 वर्षों बाद देश को पहला सहकारिता विश्वविद्यालय मिल रहा है।

देश में सहकारिता की अलख जगाने की इच्छाशक्ति से जनमानस को स्वावलंबन देने व *'सहकार से समृद्धि'* के संकल्प से देश को विकास पथ पर आगे ले जाने की दिशा में श्री शाह का कार्य निःसंदेह प्रशंसनीय और अनुकरणीय भी है। इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के पीछे उनकी मंशा बहुत पवित्र है। वे कोऑपरेटिव क्षेत्र के विकास और विस्तार करने की कोशिश में हैं और चाहते हैं कि सहकारी क्षेत्र को प्रशिक्षित मानव संसाधन की भरपाई त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से पूरा कर सकें। उन्होंने कहा है कि सहकारी यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसके डिप्लोमा और डिग्री धारकों को नौकरी मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी से हम डोमेस्टिक के साथ 'ग्लोबल वैल्यू चैन' में बड़ा योगदान करेंगे और 'न्यू एज कोऑपरेटिव कल्चर' भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगा।

वर्तमान समय में, देशभर में हजारों की संख्या में सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान फैले हुए हैं, मगर इनके पाठ्यक्रम में कोई मानकीकरण नहीं है। सहकारिता यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसे व्यवस्थित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स के अलावा सहकारी क्षेत्र में पीएचडी भी कराई जाएगी। इसके साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे सभी मौजूदा कर्मचारियों के लिए अल्पावधि सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाया जाएगा। इससे हमारे देश की युवा आबादी प्रशिक्षित होगी और सहकारिता के सोच को आगे बढ़ने वाले बौद्धिक वर्ग को हम तैयार करेंगे। श्री शाह चाहते हैं कि प्रतिवर्ष सहकारिता को बढ़ावा देने वाले लाखों युवा लोग डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट लेकर सहकारी आंदोलन में भागीदार बनें।

दरअसल, भारत में सहकारी क्षेत्र में जन सामान्य की बहुत बड़ी सहभागिता है। देश में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनने से सहकारी क्षेत्र के लक्ष्यों पर फोकस होकर कार्य हो रहा है, जिससे जन सरोकारों को बल मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि देशवासी अपने उद्यम, श्रम और अपनी गरिमा को संयोजित करने लगे हैं। ऐसे समय में, जब विश्व भर में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले शिक्षण व कौशल निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, भारत में सहकारिता को बढ़ावा देने वाले त्रिभुवन पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय के जरिए युवा संसाधन तैयार करने का संकल्प और उसके लिए सद्प्रयास निश्चय ही भारत को बेहतरीन भविष्य प्रदान करने की बड़ी कोशिश है। इस विश्वविद्यालय के जरिए सहकारी सिद्धांतों और गतिविधियों का विस्तार होगा, कोऑपरेटिव क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकी का फायदा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही, अनुसंधान और नवाचार भी बढ़ेंगे और जमीनी स्तर पर कोऑपरेटिव क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। यह देश को उत्कृष्ट सहकारिता कर्मी प्रदान करेगा। निःसंदेह, इससे सहकारी क्षेत्र के संगठनों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और प्रशिक्षित मानव संसाधन से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल नवाचार के तहत सहकारी प्लेटफार्मों पर अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर सहकारी संस्थानों का निर्माण और नई फंडिंग योजनाओं के विकास के लिए वित्तीय रणनीतियों का सृजन होने पर इससे देश का विकास सुनिश्चित होगा।■

-भारत सरकार में विशेष कार्य अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं

पुणे स्थित सहकारी प्रबंधन संस्थान वैमनीकॉम के दौरे के दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने "सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाना" शीर्षक से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के पत्रों के संग्रह का विमोचन किया। साथ ही, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर संस्थान की डीन हेमा यादव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की।

सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा हेतु शिलांग में आयोजित दो दिवसीय (10-11 अप्रैल) राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी।

इफको की मातृ इकाई एवं प्रथम यूरिया संयंत्र परिसर कलोल की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने व इफको निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कलोल प्लांट पहुंचे इफको अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी का गुलदस्ता देकर स्वागत करते प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी।

गांधीनगर में गुजकोमासोल द्वारा आयोजित ऑर्गेनिक खेती परिसंवाद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करते इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी। इस कार्यक्रम में विभिन्न उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि, कृषि विश्व विद्यालय के प्रतिनिधि और किसानों ने भाग लिया। श्री संघाणी ने इफको के नैनो उर्वरकों और ऑर्गेनिक खेती के बारे में विस्तार से बताया।

श्रीलाल शुक्ल जन्मशती उत्सव में सुप्रसिद्ध लोकगायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, किस्सागो हिमांशु वाजपेयी, जैनेंद्र सिंह और इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी।

गुरुग्राम स्थित एफएमडीआई में इफको की वार्षिक विपणन समीक्षा एवं रणनीति बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता इफको के मार्केटिंग डायरेक्टर श्री योगेंद्र कुमार ने की। इस दौरान राज्य विपणन प्रबंधकों के साथ मिलकर आगामी रणनीतियों पर मंथन किया गया।

भारत के सहकारी सेक्टर में एक नई क्रांति हो रही है। अभी तक यह देश के कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र मजबूत अर्थव्यवस्था को आकार देने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। सहकारी समितियों में सामूहिक शक्ति के साथ किसानों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने और दैनिक जीवन से जुड़ी सामान्य प्रणाली को एक बड़े उद्यमी प्रणाली में बदलने की क्षमता है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

Published on 06th May " Sahkar Uday"
RNI No. DLHIN/24/A0001
Postal Registration No.: DL(S)-17/3560/2024-26
Posting Date : 06th - 10th May
Posted at : Lodhi Road HO, New Delhi - 110003